

प्रबंध संचालक ने भोपाल शहर की विद्युत व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दिए जरूरी निर्देश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मथ्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल शहर अंतर्गत विद्युत संचालक श्री कितिज सिंहने मंगलवार को राजधानी भोपाल के साकार नगर तथा विद्युत बोर्ड पठानी क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं में एक जारी ली तथा रखरखाव कार्य को समय पर करने के निर्देश दिए। प्रबंध संचालक श्री सिंहने ने विद्युत हानि कम करने तथा बारिश के दौरान होने वाले विद्युत व्यवधान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की तथा उपभोक्ताओं की कार्यकारी कार्य को त्वरित निरामय करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए पूर्व और काल (विद्युत अवधारणा को दूर करना) समय पर अंटेंड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाइल फोन को 24 घंटे चाल रखें और उपभोक्ताओं के आने वाले फोन अटेंड करें। विजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रबंध संचालक ने कॉल सेन्टर, व्हाट्सएप चैटबॉट तथा स्थानीय वाट्सएप रूप एवं अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्युत संबंधी शिक्षणों का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को स्मार्ट मोर्टर के फायदे बताते हुए उनकी शंकाओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए।

एमपीयूडीसी की 'लोगो' तैयार करने के लिये पुरस्कार योजना

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नारीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने किए इन्हें प्रशंसनीय कार्य का शुभारंभ करते हुए एक शानदार 'लोगो' डिजाइन प्रतीत्योगिता का आयोजन किया है। यह पहल ख्वतश पोर्टल के माध्यम से जन-भागीदारी को प्रेरित करने और कंपनी की शहरी सुधार योजनाओं, शहरों में सीधोज, जलापूर्ति और अन्य अधोसंचानों से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूकता व पहचान को बढ़ावा देने के लिये की गई है। प्रतीत्योगिता में भाग लेने के लिए अन्य नागरिकों को पोर्टल पर अपना मैलिक डिजाइन फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। एमपीयूडीसी द्वारा चार्यनित विजेताओं के लिये प्रतिश्वेष पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 11 हजार रुपये, द्वितीय 5 हजार और तृतीय स्थान के लिए 2 हजार 500 रुपये की नामदार राशि शामिल है। प्रविष्टि की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक तय की गयी है। इस प्रतीत्योगिता के माध्यम से एमपीयूडीसी का उद्देश्य न केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हरित मध्यप्रदेश की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि है जो सामूहिक प्रयोगों को शक्ति देता है।

खाद्यविभाग की कार्यशाला 3 जुलाई को

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 02 दिवसीय कार्यशाला 3 जुलाई 2025 को पलाश रेसीडेंसी भोपाल में आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण में खाद्यविभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सलाइज कॉरपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जिले एवं प्रदेश के कार्यकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती राशि अरुण शमी, आयुक्त श्री कर्मचारी शर्मा एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री अनुराग वर्मा द्वारा मार्गदर्शित दिया जाएगा।

कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों विभागीयों की कार्यक्षमता में वृद्धि, उन्होंने नवीनतम नियमों, नीतियों, नवाचार, चुनौतीयों तथा विभागीय कार्यप्रणालियों की जानकारी देना, जिसमें प्रिलिंग, भंडारण, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई ऑफिस, ई सीआर, आईगोट जैसे विषय शामिल रहेंगे।

लोक निर्माण विभाग ने एक दिन में लगाए 2 लाख से अधिक पौधे

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)।

हरित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मंत्री श्री राजीव सिंह की अगुवाई में ऐतिहासिक पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस एक दिन में विभाग द्वारा प्रेषण में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कार्यतिमान स्थापित किया है, जो सतत विकास और हरियाली के प्रति विभाग की सेशक प्रीविडल फोन को दर्शाता है। भोपाल के आयोजित मूल्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पौधों का रोपण के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कार्यतिमान स्थापित किया है, जो सतत विकास और हरियाली के प्रति विभाग की दर्शाता है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस पौधों की दर्शाता है।



की सेटेलाइट मार्निंगरिंग की योजना बनाई गई है, जिसमें अहमदाबाद रिश्त भास्करचार्य संस्थान का सद्बोधन प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से पौधों की वृद्धि और संरक्षण की दिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा सकती। यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हरित मध्यप्रदेश की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि है जो सामूहिक प्रयोगों को शक्ति देता है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस पौधों की दर्शाता है।

अधिकारियों, अभियंताओं और उनके परिवर्तों से इस अभियान में संक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अब केवल भौतिक संरचनाओं के निर्माण तक समिति नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, हरित तकनीकों के उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन को अपनी कार्यशाली में प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण केवल एक नारा नहीं है, बल्कि विभाग की मूल कार्यनीति है, जिसमें अब पर्यावरणीय संतुलन को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकास की तेज़ रफ्तार के साथ प्रकृति का संरक्षण अब प्रत्येक अभियंता और अधिकारी की सामूहिक जिम्मेदारी है इसी दृष्टिकोण से विभाग ने 'लोक कल्याण संरक्षण' योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण में उपयोग हुए मिट्टी का युक्त्युक्त उपयोग करते हुए स्थायी जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन सरोवरों को विज्ञानसम्बद्ध ढांग से डिजाइन किया गया है तथा उनका सौंदर्यकरण, वक्षारोपण, सूखना पत्ता और जियो-ट्रैणिंग की जा रही है। इस योजना के तहत 500 लोक कल्याण सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

आयुक्त जनसम्पर्क ने संचालनालय में किया पौध-रोपण



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने मंगलवार को जनसम्पर्क के स्टाफ ने आयुक्त जनसम्पर्क को उनके जन्मदिवस के अवसर पर संचालनालय एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई ऑफिस, सीक्यूरिटी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न विभागों को दर्शाता है।

तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अशोक और गुलमोहर का पौधा लाया। इस अवसर पर जनसम्पर्क के स्टाफ ने आयुक्त जनसम्पर्क को उनके जन्मदिवस के अवसर पर

बाईंदी दी। इस दौरान अपर संचालक श्री जी.एस. वाधवा, अपर संचालक श्री संजय जैन एवं विभागीय अधिकारी १८१-क मंचारी उपर संस्थानों से आयोजित की जाती राशि व्यवहार की दर्शाता है।

दस्तावेज सत्यापन के लिए अध्यक्षों को सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण की दर्शाता है।

ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 5 दिवसीय खानसामा एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण संपन्न

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)।

मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 5 दिवसीय खानसामा एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम होटल प्रबंधन संस्थान भोपाल में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों पर कार्यरत समिति के समस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठोरीत्या, समस्या, संतारा, मारपाठ, बोदायो, कुरकुर, चारखेड़ा, रानेहाफल, खिवनी और उपरिखाखेड़ा ईको पर्यटन स्थलों से आयोजित की जाती है। यह कार्यक्रम विभागीय अधिकारी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठोरीत्या, समस्या, संतारा, मारपाठ, बोदायो, कुरकुर, चारखेड़ा, रानेहाफल, खिवनी और उपरिखाखेड़ा के बारे में भी जानकारी दी गयी है। इस योजना के बारे में भी जानकारी दी गयी है।



श्रीमती समिता राजौरा ने बताया कि आईएसएम के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सदस्यों द्वारा प्राप्त समस्याएँ सेवा में नियुक्ति का सप्ताह कारोबार होने की संतुष्टि और ज्ञास के बारे में भी जानकारी दी गयी है। साफ-सफाई एवं सार्वजनिक वितरण संस्थानों के बारे में भी प्रशिक्षण और एटीकेट्स के बारे में भी जानकारी दी गयी है।

प्रशिक्षण के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्राचार्य आईएसएम भोपाल डॉ. रोहित सर्पीन द्वारा समस्त प्रशिक्षणार्थियों क

विचार

मध्यमवर्गीय परिवार नहीं फ़ंसे ऋण के जाल में

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार दिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणारणि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणादाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणारणि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणादाता में होनी चाहिए अर्थात् ऋणादाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किशत एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणादाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात् संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणादाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किशत एवं इस ऋणारणि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणादाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणारणि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणादाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋग्यादाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किशत एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋग्या खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चक्रकर्ता ऋग्यादाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋग्यादाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किशत एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋग्यादाता ऋग्या की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋग्या की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋग्यादाता को बैंकों से ऋग्या प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋग्यादाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋग्यादाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋग्या की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है। भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की सुख्ता भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋग्या लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाइ देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध हैं वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋग्या के जाल में फंस जाता है।

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रतर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्रे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुग्राहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक तिमर्श का दिल्ला है।

यह केवल भाषा नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। हिन्दी को हथियार बनाकर उद्घव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा को राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुँह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्घव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे हैं, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्घव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई,

ਫੇਟ੍ਰੀ ਕੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕੋ ਰੋਕਨਾ ਬੜੀ ਹੁਨੌਤੀ

तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पासमैलारम फेज एक इलाके में एक केमिकल फैटरी में हुए विस्फोट में 34 कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन दिन पहले तार प्रदेश के नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित डी-93 से टर-दो स्थित शाम पेंट इंडस्ट्रीज केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपटें आसमान तक छूती नजर आई। करीब ढाई घंटे की मशवकरत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग की घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान न होने की बात कही है। इसी 16 जून को तार प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी से करीब दो किलोमीटर दूर यह फैट्री चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। नौ धायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि फैट्री संचालक ने पटाखे बनाने के लिए आसपास की रहने वाली महिलाओं को कम मजदूरी पर रखा था।



उन्हें केवल 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। मजदूरों को न कभी ट्रेनिंग दिलाई और नहीं आपातस्थित से निपटने का कोई प्रशिक्षण दिया गया। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होने पर कुछ दिन शोर मचता है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा होने के बाद सब शांत हो जाता है। दुर्घटनाएं रोकने की कोई योजना नहीं बनती। नहीं फैक्ट्री के श्रमिकों को दुर्घटना होने के समय की चुनौती बर्ताइ जाती है। दुर्घटना होने के समय की चुनौती के समय के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता। दुर्घटना होने पर क्या किया जाए इसका भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। फैक्ट्री लगती है कि किंतु उनका तकनीकि निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण करने वाली अधिकारी पैसे के बल पर अपने आफिस में ही बैठकर रिपोर्ट बना देते हैं। सही मायने में फैक्ट्रियों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौत का जिम्मेदार वह अमला भी है जो समय-समय पर इनके सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण करता है।

ब्रह्म और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और ब्रह्म संस्थान (षटखंडस्तु) द्वारा जारी अंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण देती है। तमिलनाडु में सामान्य निरीक्षण दर 17.0 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 25.39 प्रतिशत थी। गुजरात में सामान्य निरीक्षण दर 19.33 प्रतिशत और खतरनाक

फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 19.81 मिली। 2021 के लिए अखिल भारतीय आंकड़े सामान्य निरीक्षणों के लिए 14.65 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों के लिए 26.02 प्रतिशत थे। उपर्युक्त विवरण से लिया गया है।

खराब निरीक्षण दरों का एक कारण कर्मचारियों की कमी है। महाराष्ट्र में निरीक्षकों की नियुक्ति दर केवल 39.34 प्रतिशत थी। इसमें 122 स्वीकृत अधिकारियों में से केवल 48 कार्यरत थे। गुजरात में नियुक्ति दर 50.91 प्रतिशत रही, तो तमिलनाडु में यह 53.57 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय नियुक्ति दर 67.58 प्रतिशत थी। स्वीकृत पदों की संख्या पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या के सापेक्ष वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त रही है। 2021 में, अखिल भारतीय स्तर पर 953 स्वीकृत निरीक्षकों में से प्रत्येक को वार्षिक रूप से 337 पंजीकृत फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना पड़ता है।

मई 2024 में, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट में स्वीकार किया कि सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाणन अवसर ऑफिटरों और फैक्ट्री मालिकों या प्रबंधकों के बीच समझ के आधार पर किए जाते थे। यह संकेत देता है कि नियोक्ता भी त्रुम निरीक्षकों के समान ही दोषी हैं, और भ्रष्ट प्रथाओं की आपूर्ति पक्ष को संबोधित करना मांग पाया जाएगा।

पक्ष के सुधार के समान ही महत्वपूर्ण है।
 प्रदेश स्तर पर विशिष्ट सीमा मात्रा के साथ खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य को प्रमुख खतरे वाले कार्यस्थलों की सूची बनाए रखनी चाहिए। समें सुविधा का प्रकार, उपयोग किए गए रसायन और संग्रहीत मात्रा का विवरण हो। खतरनाक सामग्री की सूची और इन्वेंट्री को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करें, जिस तक नियामक निकाय, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, और जनता आसानी से पहुंच सकें। निरीक्षण प्रणाली को उदार बनाने के बजाय, सरकारों को आईएलओ सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करके मजबूत श्रम बाजार शासन सुनिश्चित करना होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और खतरनाक और रासायनिक पदार्थों के उपयोग को देखते हुए, सख्त निरीक्षणों की आवश्यकता है।

औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति सरकार की विफलता को दर्शाती है कि उसने पिछले घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। सुधारों और कमज़ोर शासन के नाम पर, राज्य अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता कि वह एक सुरक्षित कार्य और जीवन सुनिश्चित करे। एक प्रभावी और नैतिक श्रम निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्थक सुधारों की आवश्यकता है जो श्रमिकों और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही फैक्ट्री श्रमिकों का आपदा के समय सुरक्षा के उपाए, कैसे बचाव करें आदि का बार-बार प्रशिक्षण देना होगा। सभी उद्योगों के निरीक्षण के लिए तकनीकि विशेषज्ञों की टीम बनानी होगी। उन्हें नियमित निरीक्षण के निर्देश करने होंगे। इससे किसी दुर्घटना होने पर मौत और घायलों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। दुर्घटना होने के हालात में इन तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स करनी होगी। देखने में आ रहा है कि निरीक्षण स्टाफ की फैक्ट्री स्वामियों से मिलीभागत होने के कारण उद्योग स्वामी प्रायः प्रशिक्षित स्टाफ नहीं रखते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अगवानपुर की दुर्घटना ग्रस्त पटाखा फैक्ट्री का भी ये ही कारण रहा। फैक्ट्री स्वामी ने सस्ते के चक्रर में फैक्ट्री के आसपास रहने वाली महिलाएं रख रखी थीं। उन्हें वह मात्र तीन सौ रुपया रोज मजदूरी देता था। उनकी सामजिक सुरक्षा आदि का भी प्रबंध नहीं था।

केंद्र ही नहीं प्रदेश सरकारों को भी उद्योग स्वामियों को बताना होगा कि उनके यहां काम करने वाले श्रमिक और तकनीकि विशेषज्ञ देश की धरोहर है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्योग के साथ देश और समाज की भी है। घटना होने पर मात्र जांच के आदेश और मुआवजा देने से ही काम नहीं चलेगा। दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी भी तैयार करनी होगी। जिम्मेदार लोगों को दंडित भी करना होगा तभी जाकर ये दुर्घटनाएं रुकेगी। एक बात और यदि उद्योग में सुरक्षा मानक कड़े हों, उद्योग श्रमिकों को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण मिले तो दुर्घटनाएं ही न हों। हों तो मौत और घायलों की संख्या बहुत कम रहे। दुर्घटनाएं न हो तो उद्योग भी न मरे। दुर्घटनाएं होने से श्रमिकों के साथ एक प्रकार से संबंधित उद्योग भी मर जाता है। अधिकतर दुर्घटनाप्रस्त उद्योग के स्वामी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान, श्रमिकों को मुआवजा आदि देने के कारण बबाद हो जाते हैं। वे दुबारा से मुश्किल से ही काम को जोड़ पाते हैं। इससे देश का एक व्यापारी, एक व्यवसायी भी एक प्रकार से मर जाता है। उसका आर्थिक रूप से मरना देश की प्रगति को भी नुकसान देता है।

हिन्दी को सेतु का माध्यम बनायें, संघर्ष का नहीं

ହିନ୍ଦୀ



पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है।

भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परन्तु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी

संतवि के लिए सबसे बड़ा सवाल है।

संस्कृत के लिए खतरा बन सकता ह। फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हँगामेदार बनाने पर आमदा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना माराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के

दिल्ली सीएम के बंगले का रेनोवेशन होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले (बंगला नंबर 1, राज निवास मार्ग) में जल्द ही मरम्मत और सजावट का काम शुरू होगा। यह बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर की तरह इस्तेमाल हो रहा था। अब इसे मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली के लिए नायक बनाया जाएगा। बंगले में 24 एप्रिल को डोस्टर (चार 55 इंच और एक 65 इंच), 3 बड़े ड्रामर, 80 से ज्यादा पैंडे लगाये जाएंगे। किचन में नई मशीनें जैसे गेस होब, इलेक्ट्रिक चिमनी, माइक्रोवेव, टोस्ट प्रिल, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, 50 लीटर प्रति घंटे की आरओ वॉटर प्लॉट की सुविधा दी जाएंगी। रेनोवेशन के फलस्तू फेंज का कुल बजेट 60 लाख रुपये है। अकेले एयर कंडीशनिंग पर 11 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होगा और लाइट्स, ड्रूपर्स पर 6 लाख रुपये का बजेट रखा गया है। बंगला नंबर 1 एक टाइप वीआईआई आवास है, जिसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजिटर्स हॉल, नौकरों का कमरा, किचन, लॉन और बैक्यार्ड शामिल हैं। पिछले साल पूर्व सीएम अरविंद केरीबाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लिए लाखों रुपये खर्च किया गया था। तब भाजा ने बंगले को केरीबाल का शीशमहल बताया था।

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बाहिरी होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिवाली और सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बाहिरिंग कराई जाएगी। उद्योग महानिदेशालय ने इसकी मंजरी दी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रायल अग्रसर के अधिकारी समाज से सिंतंबर के पहले हफ्ते के बीच किया जाएगा। कल 5 ट्रायल लिए जाएंगे। ताकि यह समझाहल बताया था। दिल्ली का कृत्रिम बाहिरिंग के दौरान बढ़ने वाले स्पांग को कम करने में योग्य तकनीक कितनी कारगर है। यह फैसला 7 मई के दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। सरकार ने इस योजना को आईआईटी कानून के सहयोग से लागू करने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक, एक बार कृत्रिम बाहिरिंग करने की लागत करीब 66 लाख रुपये होगी, जबकि पूरे आंपेरेशन की खर्च 55 लाख रुपये रखी गयी। कुल मिलाकर इस प्रैटिशन पर करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपये की खर्च आएगा। दिल्ली के बाहरी इलाकों में ट्रायल होगा। ट्रायल दिल्ली के बाहरी इलाकों में किया जाएगा। इसके लिए अलीपुर, बवाना, रोहिणी, बुराड़ी, पाली सकपुर और कुड़ी बांडर के इलाकों को चुना गया है। कलाड़ सीडिंग 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले यह ट्रायल जल्दी में होना था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के सुझाव पर इसे टाल दिया गया।

हिमाचल में 30 जून की रात 16 जगह बादल फटे

नई दिल्ली (एजेंसी)। 30 जून की रात के बादल फटने से पटिकरी पावर प्रॉजेक्ट परी तरह से तबाह हो गया। 12 कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में 20-21 जून को मानसून की एंटी हर्फ थी। अब तक 20 से ज्यादा जगह बादल फटने की घटना हो चुकी हैं। अकेले 30 जून की रात मंडी और किनारे में 16 जगह बादल फटे थे। इस मानसून में राज्य में लैंडस्लाइड-बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 से ज्यादा लोग लापता हैं। 40 के करीब मकान पूरी तरह ढह गए हैं। मंडी जिले से बहने वाली व्यास नदी उफान पर है।

जैसलमेर की सड़क पर उतरे सेना के हेलिकॉप्टर

जैसलमेर (एजेंसी)। इसी सवाल का जवाब ढूँढ़ने के लिए भारतीय सेना ने आज जैसलमेर में युद्धाभ्यास किया। जहां चीता और चेतक हेलिकॉप्टर सहित अन्य लड़ाकू हेलिकॉप्टर सड़क पर उतरे और अतिक्रियों को खत्म कर वापस हेलिकॉप्टर में चढ़कर उड़ान भीरी। इसे हेलिकॉप्टर आंपेरेशन कहा जाता है। राजस्थान के थार इलाके में भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने हाई-ट्रैक्सीटी युद्धाभ्यास किया गया, जिसमें युद्ध के हर पहलू को व्यावहारिक स्तर पर परखा



गया। इस अभ्यास में सेना के टैंक भी शामिल हुए और टारोट को सफलतापूर्वक नष्ट किया। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक के बाप्सरसाइज की गई।

हरियाणा सरकार 8 हजार घर गिराएगी

फरीदाबाद (एजेंसी)। किया गया तो 10 जुलाई के हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फलाईओवर के लिए 8 हजार मकानों के खाली कराकर गिराने की चैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पूर्वांस के बीच रहने के लिए 50 साल से यहां रह रहे हैं। चुनाव में वोट भी करते हैं, अगर सरकार घर छोंग ले रही तो वे कहा जाएंगे। उठर, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि वे किसी भी किमत पर ऐसा नहीं होने देंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केरीबाल पर किया कटाक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में जीर्णोद्धार के बाद शीश महल का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केरीबाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक शीश महल जनता के पैसे से अपनी आयाशी के लिए बनाया गया था, जबकि आज निश शीश महल का उद्घाटन हो रहा है, वह जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विशेष

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का माना आभार

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री मित्रा पार्क के प्रथम चरण में अधोसंचान विकास को प्रक्रिया आरंभ होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिज शिंह का हृदय में आभार माना है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा धार की 2158 एकड़ भूमि पर लगभग 2050 करोड़ की लागत से विकसित हो रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिए हाल ही में 773 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पहल मध्यप्रदेश में कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल सेक्टर) को नई गति प्रदान करेगी। मध्यप्रदेश लगातार विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी



द्वारा दी गई प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुधारांभ करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नए युग का शुभांभ करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी में 20 एमएलडी शृन्य अपशिष्ट जल निकास और कपड़ा उद्योग में नए युग

मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी का इस दूरदृश्य योजना के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अब तक 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए चुंबे हैं, जो उद्योग जगत के उत्साह को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र को मध्यप्रदेश से नई ऊर्जा और दिशा देगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की व्यापक बल

कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन कार्डिनल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कैविनेट की लागत करीब 66 लाख रुपये रखे। कुल मिलाकर इस प्रैटिशन पर करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपये की खर्च आएगा। दिल्ली के बाहरी इलाकों में ट्रायल होगा। ट्रायल दिल्ली के बाहरी इलाकों में किया जाएगा। इसके लिए अलीपुर, बवाना, रोहिणी, बुराड़ी, पाली सकपुर और कुड़ी बांडर के इलाकों को चुना गया है। कलाड़ सीडिंग 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले यह ट्रायल जल्दी में होना था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के सुझाव पर इसे टाल दिया गया।

मीडिया के सवालों पर भड़के सिद्धारमैया

चिकित्सक (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बुधवार को कहा कि वे पूरे पांच साल तक बृहत् प्रधान देने के अलावा कोई बाहरी इलाकों के लिए बृहत् नहीं है। इसके पछले भी शिवकमार ने कहा कि किंतु उनसे ज्यादा असंतोष नहीं है। और जब जिले में इसके लिए बृहत् नहीं हैं, तो नेतृत्व के मुद्रे पर किसी तरह के विवाद का कोई जरूरत नहीं है। पार्टी अनुशासन महत्वपूर्ण है, मैंने किसी से खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहा है। भाजा और जेडी(एस) के इस दावे पर कि सीएम को बदला जाएगा, सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए कहा- क्या वे हमारे द्वारा किया गया है। उनका दावा नहीं कहा जाता। इसके बाद जिले में इसके लिए बृहत् नहीं हैं, तो नेतृत्व के मुद्रे पर किसी तरह के विवाद का कोई जरूरत नहीं है। पार्टी अनुशासन महत्वपूर्ण है, मैंने किसी से खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहा है। शिवकमार ने यह चेतावनी भी दी कि सीएम बदलने के मुद्रे पर सावित्रिक बयान देने वाले नेताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। मई 2023 में विधानसभा चुनाव के नरीजे थोकित होने के बाद बृहत् अंतर्कालीन एक बृहत् संघर्ष हो गया है। आरोपियों को क्रांति चाहिए या नहीं है। इधर, उपमुख्यमंत्री शिवकमार के बीच कट्टी प्रतिस्पर्धा थी, और शिवकमार के बीच कट्टी

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक संपन्न शासन की योजनाएं समयबद्ध तरीके से हो पूरी, कलेक्टर ने अफसरों को दिए स्पष्ट निर्देश

"समय पर काम नहीं तो जबाबदेही होगी तथा" योजनाओं की गुणवत्ता और गति दोनों पर होगी अब सख्त निगरानी

मीडिया ऑँडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले की सांसाक्षिक समय सीमा की समीक्षा बैठक आज कलेक्टर सभाकक्ष में केलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिद्धर, किनारक शर्मा तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपाल अधिकारी तथा कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत के सीआई, तहसीलदार, नगर निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की प्राप्ति, लिखित कार्यों, पंचायत स्तर की समस्याओं तथा विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के सीआई, तहसीलदार, नगर निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।



हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं समस्त जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के सीआई, तहसीलदार, नगर निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

</div